single foliar application of NAA (Naphthalene Acetic Acid) at 200 ppm in the mon h of October followed by deblossoming at bud burst stage have been found to be effective in reducing the incidence of malformation.

गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के माध्यम से वृक्षारोपण

*381. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से अधिकाधिक वृक्षारोपण कराने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वृक्षारोपण के लिए कितने एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है और उसकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) वृक्षारोपण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं और उनके माध्यम से वृक्षारोपण अभियान चलाने में क्या कठिनाई अनुभव की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1983-84 में छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना शुरू की गयी है। योजना का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ग) यह योजना प्रमुख रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के लाभ के लिए तैयार की गयी है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़ा वर्ग भी शामिल हैं। यह नये 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत अपने आपमें प्राथमिकता की मद है। छोटे तथा सीमांत किसानों की जिन सहकारी समितियों की अपनी निजी भूमि हो वे भी नई योजना से लाभ उठा सकती हैं। अभी तक किसी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

"छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता" नामक योजना का ब्यौरा

(क) और (ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता करने सम्बन्धी कार्यक्रम में 1983-84 के दौरान 250 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। यह देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रति खण्ड 5 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) छोटे तथा सीमान्त किसानों को कुओं और पम्पसेटों पर समेकित ग्रामीण विकास के प्रतिमान के अनुसार 50% की सीमा तक राज सहायता	3.50 लाख रुपए
(2) छोटे तथा सीमान्त किसानों की जोतों पर जलावन तथा फल देने वाले वृक्षों के रोपण के लिए समेकित ग्रामीण विकास के प्रतिमान के आधार पर 50% की सीमा तक राज सहायता	0.50 लाख रुपए
(3) तिलहनों तथा दलहनों के उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिटों	

के निःशुल्क वितरण और आदानों भूमि, विकास तथा स्टाफ पर आने वाली लागत के लिए एकमुश्त आबंटन 1.00 लाख रुपए

योग : 5.00 लाख रुपए

छोटे तथा सीमान्त किसानों की जोतों पर जलावन तथा फल देने वाले वृक्षों के रोपण के लिए 50,000 रु० का प्रावधान किया गया है, जो नर्सरियां तैयार करने और मुफ्त या दस पैसे प्रति पौध के हिसाब से मामूली शुल्क लेकर पौधों की सप्लाई करने के लिए हैं। प्रत्येक ब्लाक के लिए 80,000 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे तथा सीमान्त किसान को अपनी निजी भूमि में फल देने वाले अथवा जलावन वाले कम-से-कम 25% पौधे लगाना आवश्यक है।

Development of Regulated Markets

*382. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government of India are having any scheme to provide assistance to State Governments for the development of regulated markets; and

(b) if so, details thereof and the amount, if any, given to Kerala under this scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) Yes, Sir.

(b) Under the scheme for development of selected regulated markets, central assistance is given at the following rates for providing infrastructural facilities for agricultural markets which meet the requirements of the scheme :

(i) Regulated Markets handling commercial crops (Jute, Tobacco, Cotton, Groundnut, Cashewnut, Coconut, Potatoes, Onion, Betal, leaves, and chillies)
Rs. 4 lakhs per market.

(ii) Regulated markets situated in command areas
Rs. 5 lakhs per market.

(iii) Terminal Markets for Fruits and Vegetables.
Rs. 15 lakhs per market.

Kerala State has not so far availed of any central assistance under the scheme.

Projects to Increase Groundnut Production in Gujarat

*383. SHRI MOHANLAL PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the short and long term measures which have been included in launching the special project on groundnut in Gujarat;

(b) what has been the increase in production of groundnut as a result of the special measures taken; and

(c) what other steps are being taken to increase the production of groundnut in the country, particularly in Gujarat State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The short and long term measures included in the special project for increasing groundnut production in Gujarat are:—

(i) distribution of quality seeds;